बीके अस्पताल में सीटी स्कैन व एमआरआई की मारीचिका ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) जनता को बेहतर एवं सस्ती चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने का दावा भाजपा सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से भी बढ-चढ कर किये जा रही है। इस दावे के तहत यहां के प्रमुख सरकारी बादशाहखान अस्पताल में सीटी स्कैन व एमआरआई मशीनें लगाने का ढोल सरकार लगातार गत 6-7 माह से पीट रही है। लेकिन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार, जिसका जनता की चिकित्सा सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं है, ने उक्त दोनों मशीनों को लगाने व चलाने का ठेका एक निजी कम्पनी (प्रकाश हॉस्पिटल) को दे दिया है। इस ठेके अथवा दुकानदारी को आधुनिक सौम्य भाषा में पीपीपी मोड कहा गया है। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यह सेवा कब तक शुरू हो जायेगी तथा इसके रेट क्या होंगे, जानने के लिये बीके अस्पताल प्रमुख डॉ. सुरेश से बात की गयी। उन्होंने पूरी जानकारी न होने की बात कहते हुए प्रकाश हॉस्पिटल नौयडा का फ़ोन नम्बर थमा दिया। इस कम्पनी के प्रवक्ता नवनीत ने बताया कि उनकी एक मशीन सीटी स्कैन तो बीके अस्पताल पहुंच चुकी है तथा दूसरी पहुंचने के लिये एकदम तैयार है। इन मशीनों को लगाने की जगह तो अस्पताल ने दे दी है लेकिन इसके लिये आवश्यक 360 किलोवाट बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। जब तक यह कनेक्शन नहीं मिल जाता मशीनें चालू नहीं हो सकतीं। आगे नवनीत ने बताया कि एमआरआई मशीन में हर समय बिजली का रहना अति आवश्यक है। यदि बिजली न रहे तो मशीन में भरा दो से तीन लाख रुपये का तरल एकदम उड़ जाता है। ''आप इन सेवाओं के लिये मरीज़ों से क्या फ़ीस लेंगे?'' जवाब में उन्होंने बताया कि जों सरकार ने रेट तय कर रखे हैं उनसे तो कम ही लेंगे, बीके अस्पताल के मरीज़ों से और बाहरी मरीज़ों से मार्केट के हिसाब से ज़्यादा पूछने पर उन्होंने बताया कि इन मशीनों पर कोई एक तरह का काम तो होता नहीं, किसी का पेट का है तो किसी के सिर या टांग का है तो काम के हिसाब से ही रेट तय होते हैं। अपनी कम्पनी के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वे कोई मुनाफ़ाखोरी के लिये नहीं बल्कि जनता की सेवा के उद्देश्य से यह काम करने फ़रीदाबाद आ रहे हैं।

'सेवा भाव' की बात सुन कर सवाल उठा कि इस सारे काम पर खर्चा क्या आने वाला है? नवनीत ने बताया कि सीटी स्कैन करीब 2 करोड़ और एमआरआई पर 6 करोड़ का खर्च आयेगा जो सारे का सारा उनकी कम्पनी वहन करेगी। काम करने वाला सारा स्टाफ़ भी कम्पनी का ही होगा। अस्पताल की तो केवल जगह और बिजली होगी। बिजली का बिल कम्पनी भरेगी या अस्पताल, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

मामला गम्भीर है। जो सरकार जनता की सेवा करने के नाम पर भारी-भरकम टैक्सों की वसूली करती है सत्ता में आने के लिये दुनिया भर के वायदे एवं आश्वासन देती है, उससे तो जनता की सेवा हो नहीं पा रही; ऐसे में प्रकाश हॉस्पिटल जैसी कोई कम्पनी पल्ले से 8 करोड़ खर्च करके जनता की सेवा करने आ रही है, बात कुछ हजम नहीं हो रही। और मान लो यह कम्पनी सेवा करना भी चाह रही हो तो जगह-जगह बैठे सरकारी लक्कड़बग्घे क्या कुछ करने देंगे? सबसे पहले तो बिजली वाले ही। जब उन्हें पता लगेगा कि बिजली इस कम्पनी की जान है तो वे ही सबसे पहले इनकी जान के ग्राहक हो जायेंगे। क्योंकि 360 केवी का बैक अप इस कम्पनी के पास होगा नहीं और अस्पताल का अपना जनरेटर भी कुल 300 केवी का ही है जो अव्वल तो खराब रहता है और यदि चल जाये तो पूरे अस्पताल के लिये ही अपर्याप्त रहता है, ऐसे में वह कम्पनी की इन कीमती मशीनों को क्या सम्भालेगा?

इन हालात में उक्त कम्पनी व सरकार मिलकर जनता को कैसी सेवायें दे पायेंगी समझना कठिन नहीं है, बाकी समय आने पर पता चल पायेगा।

कहां-कहां और क्यों लगता है जाम, पुलिस 'पता' लगायेगी

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 21 अगस्त को प्रकाशित एक तथाकथित राष्ट्रीय दैनिक में शहर के संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय सिंह की ओर से कहा गया है कि वे शहर के तमाम थाना प्रभारियों की मीटिंग बुला कर उनसे, अपने-अपने क्षेत्रों में जाम लगने वाले विशेष स्थानों को चिन्हित करेंगे तथा जाम के कारणों को खोज कर उनका निदान भी करेंगे।

इस पुलिस एवं प्रशासन के हाथों जाम से निजात पाने की आस लगाये बैठी जनता के लिये स्पष्ट संदेश है कि जिस पुलिस को अभी तक यही नहीं पता कि जाम कहां-कहां और क्यों लगता है, वह जाम क्या खाक सुलझायेगी। शहर की लगभग हर सड़क पर सारे शहरवासियों को जाम लगा हुआ साफ़ नज़र आता है और जाम के कारण भी वहीं पर दिखाई देते हैं। लेकिन शहर की ट्रैफ़िक व्यवस्था के मुखिया संजय साहब को यह कहीं दिखाई नहीं दे पा रहा। इसके लिये बाकायदा थाना प्रभारियों की मीटिंग होगी, कब होगी अभी पता नहीं। उसके बाद कब तक थाना प्रभारी अपनी रिपोर्ट साहब बहादुर को प्रस्तुत करेंगे पता नहीं। रिपोर्ट पढने के बाद साहब बहादुर उस पर कब और क्या कार्यवाही करेंगे पता नहीं। तब तक कोई नये साहब बहादुर आ जायेंगे।

सन् 2008 में जब श्रीनिवास वशिष्ठ आईजी रेंज यहां तैनात होकर आये थे तो उनसे अनौपचारिक बातचीत में इस संवाददाता ने शहर की लचर ट्रैफ़िक व्यवस्था एवं जाम की समस्या का उल्लेख किया था। उस वक्त वशिष्ठ साहब ने इसे तुरंत सुधारने के साथ-साथ कोई चार ऐसे स्थान बताने को कहा जहां हालत सबसे बुरी हो। उस वक्त उन्हें कम से कम 8 स्थानों के नाम बताये गये थे। उनमें से एक स्थान (बल्लबगढ) की हालत अब कुछ दुरूस्त हुई है वह भी वहां के एसएचओ की पहल पर।

इसके बाद एक ड्रामा शुरू किया था उपायुक्त प्रवीण कुमार ने। उनके कहने पर नगर निगम ने ट्रैफ़िक ज़ाम की वीडियोंग्राफ़ी कराई। ट्रैफ़िक विशेषज्ञों से विशेष रिपोर्टें बनवाई गयी। इस सब पर लाखों रुपया तो बर्बाद हुआ लेकिन ज़ाम के हालात जस के तस बने रहे।

दिनांक 20 अगस्त को दोपहर 12 बजे ज़िले के सैशन जज साहब तिकोना पार्क वैष्णो देवी मन्दिर के पीछे वाली सड़क पर करीब 15 मिनट तक जाम में फ़ंसे रहे। और ज़्यादा देर भी फ़ंसे रहते यदि उनका बन्दूकधारी सिपाही उनके लिये रास्ता न खुलवाता। जैसे-तैसे जज साहब तो जाम से निकल गये, लेकिन जनता को इस जाम से कैसे निजात दिलाई जाय इस पर भी यदि जब साहब कुछ सोचते तो बेहतर होता।

जाम का एक बड़ा कारण असुरक्षित एवं टूटी-फूटी खड्डेदार सड़कें व अतिक्रमण भी हैं । इन दोनों समस्याओं से निपटना अकेले पुलिस के बस का नहीं है। इसके लिये तमाम (सम्बन्धित) प्रशासनिक अधिकारी व राजनेता ज़िम्मेदार हैं। चार बूंद पानी बरसा नहीं कि सड़कें डूब जाती हैं। और ज़रा ज़्यादा पानी बरस गया तो फ़िर क्या कहने, फ़िर तो बाढ की सी स्थिति बन जाती है। वाहन सड़कों पर फंस कर खड़े हो जाते हैं। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा बनवाई गयी सड़कें धंस जाती हैं, गड्ढों की तो गिनती ही नहीं रहती।

शहर के एसजीएम नगर की गलियों में नारियल फ़ोड़ने में व्यस्त स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल ने एक पत्रकार को आश्वासन दिया कि बरसात के बाद सड़कों की तुरन्त मुरम्त करने के आदेश अधिकारियों को दे दिये गये हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य पूरा होने तथा मैट्रो रेल चलने के बाद जाम से निजात मिल जायेगी।

लेकिन मंत्री महोदय से न तो किसी ने पूछा और न उन्होंने बताया कि आखिर सड़कों पर ही पानी क्यों खड़ा होता है? सड़कों के कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जहां से पानी कभी निकल ही नहीं सकता, जब तक स्वत: सूख नहीं जाता वहीं पड़ा सड़क तोड़ता रहता है। सर्वविदित है कि प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये सड़कों के नवनिर्माण एवं मुरम्मत पर खर्च दिखा कर हड़प लिये जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सड़कें सदा ही टूटी-फूटी रहती हैं। इसका समाधान मन्त्री जी क्यों नहीं करते?

ध्यान रहे कि अनिल अम्बानी ग्रुप द्वारा किये जा रहे हाईवे निर्माण ने जाम को और बढाने में ही योगदान दिया है। राजनीतिकों ने पैसे खाकर, राजमार्ग निर्माण की शुरूआत के बरसों पहले से अनिल अम्बानी को टोल उगाही का लाइसेंस दे रखा है। इसके फलस्वरूप निर्माण कार्य भी बिना किसी जवाबदेही के चलाया जा रहा है। बरसों की देरी हो चुकी है और आलम यह है कि सड़क की जगह सड़क ही नहीं बची हुई। अब जाम न लगे तो क्या?

नगर निगम चुनाव: जीतने के लिये भेंड़ियों ने ओढी भेंड़ की खाल

फ़रीदाबाद (म.मो.) आगामी दो-तीन माह में नगर-निगम चुनावों की संभावना के मद्देनज़र अलग-अलग वार्डों से छुटभैये नेता कुकरमुत्तों की तरह बाहर आ गये हैं, व चुनाव लड़ने को बेकरार हैं। कई उम्मीदवार तो सांसद व विधायकों के घर के बाहर लाईन लगा कर खड़े, देखे जा सकते हैं। इनमें से एक का भी जनसेवा से कोई लेना-देना नहीं है। बल्कि ये सब तो किसी भी तरह से जीतकर पूरे 5 साल तक लूट का पट्टा हासिल करना चाहते हैं। नगर निगम चुनावों को लेकर वार्ड नम्बर 11 में तो एक छुटभैया नेता विजेन्द्र गोला ने तो इन दिनों बाकायदा महिलाओं व बुजुर्गों के लिए ई-रिक्शा तक मुफ़्त चला दिया है। जबकि पूरी उम्र इस उम्मीदवार व इसके दोनों भाईयों ने 2 नम्बर नागा बाबा कॉलोनी में शराब बेचने का धंधा कर बैंकों से फ़ाइनेंस गाड़िया उठाने, कब्ज़े की प्रोपर्टी खरीदने व बेचने का धंधा किया। गुंडा गिरोह के बल पर मोटा ब्याज वसूली भी उनका धंधा है। शहर का शायद ही कोई ऐसा थाना चौकी हो जिसमें इनके खिलाफ़ मामला न गया हो।

अभी पिछले दिनों भी इसका बड़ा भाई धर्मपाल कई महीने नीमका जेल में हवा खाकर आया है। वही वार्ड नम्बर 14 में दो दर्जन से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतरने की तैयारी में है। इस वार्ड में तो टेलर से लेकर ब्यूटी पार्लर चलाने वाले व कब्ज़ा की प्रोपर्टी खरीदने बेचने व सट्टा का धंधा करने वाले भी पोस्टर बोर्ड लगा कर जनता की सेवा करने का दम भर रहे हैं। इसी वार्ड में केसी रोड स्थित एक गेस्ट हाउस मालिक ने भी अपना चेले पर दांव खेला है व उसे चुनावी मैदान में उतारा है व उसके पोस्टर शहर में लगाकर उसे पार्षद बना, दिया है। वही इसी वार्ड से विधायक सीमा त्रिखा के खासमखास सरदार जसवंत सिंह व संदीप कौर (रीटा) भी चुनावी मैदान में है। इन्होंने बोर्ड लगाकर वार्ड नम्बर 14 की गलीयां व सड़के भर दी हैं। सरदार जसवंत सिंह ने जहां सीमा त्रिखा के लिये वोट मांगे थे वहीं सीमा त्रीखा द्वारा आयोजित प्रगति रैली में संदीप कौर ने कई बसें लगाकर काफ़ी रुपये फूके थे। यह बात अलग है कि सीमा त्रिखा ने संदीप कौर को मंच के आस-पास भी फटकने नहीं दिया। वहीं वार्ड में व सोशल मीडिया पर सीमा त्रिखा के साथ बोर्ड लगाकर अपने आप को भावी पार्षद देख रहे हैं। जबकि असलियत में इन दोनों ने ही कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया जिसको लेकर जनता इन्हें वोट दें। जिस तरह पूर्व मंत्री ए.सी. चौधरी अपने वफ़ादार नरेश गोसाई व चारू गोसाई के लिए गली-गली घूम कर वोट मांगता है उसी तर्ज पर विधायक सीमा त्रिखा भी अगर घूमे व वोट मिल जाए तो वो बात अलग है।

वहीं इसी वार्ड से एक उम्मीदवार की तो कहानी ही अलग है। जिसका समाज सेवा से कोई लेना-देना नहीं है। पूरी उम्र एस्कॉर्ट कंपनी में नौकरी कर गुजार दी व अब कंपनी से मिले लाखों रुपये को चुनाव पर लागाने की तैयारी में है। व अपने फ़ोटो व अपने पिता की फ़ोटो लगाकर पोस्टर वार्ड में लगाकर पार्षद बनने के सपने देख रहे हैं। वहीं एन.एच. 5 में अन्डे बेचने का धंधा करने वाला साहिल अरोड़ा भी पार्षद पद के सपने देख रहा है। व विधायक विपुल गोयल का छोटा भाई होने का दावा करता है व एनएच 3 से चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है। वही वार्ड नम्बर 14 से संदीप कौर जहां लंगर बांट कर जन सेवा करने का दावा केर रही है वही असलियत में उनके पड़ोस में रहने वाले भी उसे नहीं पहचानते।

सूत्रों अनुसार वार्ड नम्बर 14 के उम्मीदवारों ने बाकायदा एनआईटी थाना में सैटिंग कर रखी है कि अगर 5 नम्बर केजेएच दुकानदारों, ब्लॉक वालों के झगड़े की कंपलेन आती हैं। तो वो उन्हें फ़ोन कर थाने में बुलाले जिससे वो दोनों पक्षों को समझा-बुझा कर फ़ैसला करवा दंगे। उनके नंबर बन जाए व पुलिस का खर्चा निकल आयेगा।

वार्ड 11 से एक उम्मीदवार विजेन्द्र गोला के 2 नम्बर नागा बाबा कॅलोनी स्थित घर पर बिजली चोरी का मामला सामने आया था। वह बात अलग है कि इस कॉलोनी के अधिकांस घरों में बिजली के मीटर हैं ही नहीं और वे सभी 'कुंडी कनेक्शन' से ही काम चलाते हैं। दूसरी वार्ड-14 से संदीप कौर सीमा त्रिखा के साथ-साथ कृष्णपाल गुर्जर के घर पर भी चक्कर काट रही है। व जल्द ही के.का रात्री भोज भी करने वाली है।

मोदी व खट्टर के इन्तज़ार में खड़े-खड़े जंग खा रही मैट्रो

फ़रीदाबाद (म.मो.) जुलाई के अन्तिम सप्ताह में चलने के लिये पूरी तरह से तैयार मैट्रो फ़रीदाबाद तक इसलिये नहीं चल पाई कि कभी देश के प्रधानमंत्री मोदी तो कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को समय नहीं मिला हरी झंडी दिखाने का। दोनों ही अपने-अपने स्तर पर जुमलेबाज़ी और देशी-विदेशी सैर सपाटों में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हैं।

खट्टर साहब 15 अगस्त की रात को पूरे लाव-लश्कर के साथ 10 दिन को अमेरिका व कनाडा घूमने निकल गये। यदि खट्टर साहब 10 दिन की छुट्टियों पर विदेश घूमने की बात साफ़-साफ़ कह देते तो इस पूर्व संघी प्रचारक के विरुद्ध बवाल खड़ा होना तय था। इसलिये सद्बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी इस यात्रा का उद्देश्य विदेशी निवेश हरियाणा में खींच लाना बताया। खट्टर से पहले के मुख्यमंत्री भी ऐसा ही पाखंड करके विदेश यात्रायें करते रहे हैं। सभी जानते हैं कि विदेशों में बैठे पूंजीपति एवं उद्यमी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो इनके बहकावे में आकर यहां की लालफ़ीताशाही में अपनी पूंजी फ़ंसा बैठें। उन्हें वहां बैठे ही देश के हर कोने की सारी हक़ीकत का पता रहता है। वहां बैठे ही उन्हें यहां की टूटी सड़कें, पावर कट, लाल फ़ीताशाही एवं भ्रष्टाचार के साथ-साथ बिगड़ती कानून व्यवस्था दिखाई दे रही है। करदाता के करीब ढाई हज़ार करोड़ रुपये खर्च करके बनाई गयी मैट्रो रेल में क्या तो मनोहर लाल खट्टर का योगदान है और क्या नरेन्द्र मोदी का, यह फ़रीदाबाद की जनता से छिपा नहीं है। इन दोनों के सत्तारूढ होने से पूर्व मैट्रो रेल कार्पोरेशन ने अपना काम काफ़ी हद तक पूरा कर लिया था। यदि इन दोनों की जगह कोई और लोग सत्ता में आते तो भी इस मैट्रो ने यूं ही बनना और चलना था। इन दोनों द्वारा हरा झंडा दिखाये बिना भी इस रेल को चलना आता है। बल्कि जिस दिन ये लोग उद्घाटन का पाखंड करेंगे उस दिन सुरक्षा के नाम पर आम जनता की जो फ़जीहत होगी वह अलग से।

दरअसल इस देश में एक ऐसे कानून की सख्त जरूरत हैं जो तमाम छोटे-बड़े नेताओं द्वारा किये जाने वाले उद्घाटनों व शिलान्यासों पर सख्ती से पाबंदी लगा सके। जनता के खर्चे पर जनता की परेशानी को बढ़ा कर उक्त दोनों कामों से नेतागण अपार सन्तुष्टि अनुभव करते हैं। स्थानीय कृष्णपाल जैसे नेता को किसी बड़े शिलान्यास या उद्घाटन का मौका नहीं मिलता तो वे शहर की गलियों में ही नारियल फ़ोड़-फ़ोड़ कर इस सुखद एहसास को अनुभव कर लेते हैं।

इस सुखद एहसास के पीछे मंत्रियों को दरअसल एक बड़ा भारी भ्रम यह भी रहता है कि ऐसे पाखंडों के करने से जनता उनकी अहसानमंद हो जाती है; जनता यह समझती है कि यदि ये नेतागण शिलान्यास अथवा उद्घाटन न करते तो उन्हें यह सुविधा मिलने वाली नहीं थी। लेकिन नेतागण जितना जल्दी इस भ्रम को दूर कर लें उतना ही उनकी सेहत के लिये मुफ़ीद होगा, क्योंकि यह जनता है जो सब जानती है।

मैट्रो रेल को मोदी-खट्टर के हाथों जनता को सौंपने की इस देरी से जहां मैट्रो रेल को 20 से 25 लाख का नुक्सान प्रतिदिन हो रहा है, वहीं करीब 2 लाख यात्री परेशान हैं जो मैट्रो की सुविधा से जबरन वंचित रखे जा रहे हैं। भाजपाई नेताओं को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि उनके इस पाखंड से उनके वोट बैंक में कोई वृद्धि होने की बजाये कटौती होने जा रही है; क्योंकि लोग़ों में इस अवांछित देरी को लेकर काफ़ी गुस्सा है जिसे वे वक्त आने पर प्रकट करने से नहीं चूकेंगे।

मोदी द्वारा इस उद्घाटन के साथ-साथ शहर में एक रैली की तैयारी के लिए तमाम ज़िला प्रशासन एवं पुलिस सारे काम-काज छोड़कर रैली की तैयारियों में जुटे हैं; इतना ही नहीं चंडीगढ तक से उच्चाधिकारी यहां चक्कर काट रहे हैं। यानी रैली के नाम पर जनता के लिये एक और मुसीबत। शहर भर में सुरक्षा के नाम पर जो ड्रामे होंगे उनसे जनता की परेशानियां तो बढेंगी ही।

जनता की परेशानियां बढाने में रेलवे भी पीछे नहीं रहना चाहती। उसने भी इन्हीं दिनों में इंटरलाकिंग के नाम पर रेल सेवा ठप कर रखी है। दैनिक यात्रियों द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद भी रेलवे इस काम को मैट्रो रेल के शुरू होने तक टालने को राज़ी नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप दैनिक यात्रियों के लिये दिल्ली आना-जाना टेढी खीर बना हुआ है। वैसे भी जब देखो तब रेलवे वाले कभी इन्टरलाकिंग तो कभी सिग्नल के नाम पर आये दिन रेल सेवा ठप किये ही रहते हैं।